BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 25th March, 2015 | No. 6

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने चैम्बर सदस्यों को बताया

बिहार में सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा प्रभावी

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारि शरण के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 19 मार्च, 2015 को एक बैठक आयोजित हुई। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उद्योग मित्र के कार्यपालक अधिकारी श्री विमल कुमार भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि चैम्बर एवं उद्योग विभाग का संबंध अटूट रहा है और चैम्बर राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास हेतु उद्योग विभाग के सभी रचनात्मक कार्यो में सदैव सहयोग देता रहा है और भविष्य में भी सहयोग देता रहेगा।

श्री साह ने कहा हमारे राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति काफी प्रगतिशील एवं आकर्षक है और इसी के फलस्वरूप तमाम् बाधाओं के बावजूद राज्य में करीब 8000 करोड़ रूपये का निजी निवेश हो चुका है। लेकिन आकर्षक नीतियों के बावजूद Delivery Machanism में खामियाँ हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। उद्यमियों को सम्मान देने की आवश्यकता है जो कि एक Confident Building Measure का काम करेगा। श्री साह ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री शरण साहब के नेतृत्व में उद्योग विभाग इस दिशा में अवश्य सकारात्मक कदम उठाएगा।

श्री त्रिपुरारि शरण, प्रधान सचिव को बुके देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

श्री साह ने प्रधान सचिव को एक ज्ञापन भी समर्पित किया जिसके मुख्य विन्दु हैं:- उत्तर बिहार से कच्चा माल और तैयार माल दक्षिण बिहार नहीं जा पा रहा है और ना ही दक्षिण बिहार का कच्चा माल/तैयार माल उत्तर बिहार जा पा रहा है। क्योंकि गाँधी सेतु और मोकामा के राजेन्द्र सेतु पर भारी वाहनों का परिचालन बन्द कर दिया गया है। मजबूरन छोटी गाड़ियों से माल मंगवाना पड़ रहा है जिससे उद्योगों की लागत काफी बढ़ जाती है। अत: सरकार के स्तर पर दीघा रेल-सह-सड़क पुल एवं मुंगेर पुल को शीघ्र चालू कराने का प्रयास किया जाए।

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना हेतु कारगर कदम उठाया जाए। Unutilised राशि को वैट की प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य-कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए। सिंगल विंडो की दुर्दशा की ओर घ्यान आकृष्ट करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि वहाँ उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है। प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को सरकार की नीतियों एवं सिंगल विंडो सिस्टम की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्कता है। उद्योगों हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए विशेष घ्यान देने की आवश्कता है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की पूर्णरूपेण कार्यान्वयन, उद्योग संबंधित करों के संबंध में सामग्री खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार, चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार करने, प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता, गैस पाइप लाइन जो बिहार के अनेक स्थानों से होकर गुजरेगी, उसका अधिकतम लाभ लेने और इसे शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास, राज्य के सभी वित्तीय संस्थानों के लगभग बंद होने के फलस्वरूप उद्यमियों को ऋण उपलब्धता के अभाव के आलोक में इन वित्तीय संस्थानों का पुनरूद्धार, डेयरी उद्योग की स्थापना हेतु सरकार के निर्णय का स्पष्टीकरण, राज्य में बैंको द्वारा ऋण प्रभाव बढ़ाना, फुड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराने, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति की फीस उद्योगों की Fixed लागत पर निर्धारित किया जाना अनुचित है, इसमें कमी करने जैसी मांगे प्रमुख हैं।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योग उप-समिति के चेयरमैन श्री पी० के० अग्रवाल ने ज्ञापन के विन्दुओं पर विस्तृत रूप से प्रधान सचिव का घ्यान आकृष्ट किया।

बैठक में उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, मुजफरपुर के श्री कृष्ण मुरारी टिकमानी, श्री एम० पी० बिदासरिया, श्री रामलाल खेतान, श्री भरत अग्रवाल, श्री संजीव कुमार चौधरी ने भी उद्योग, वियाडा, वैट, बैंको द्वारा ऋण स्वीकृति नहीं किया जाना आदि समस्याओं पर प्रधान सचिव, उद्योग का घ्यान आकृष्ट किया एवं अपने सुझाव भी दिये।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारि शरण ने सदस्यों को सुनने के बाद कहा कि ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं में से कुछ तो नीति मूलक हैं जिनके विषय में प्रतिबद्धता दिखाना मेरे लिए युक्तिसंगत नहीं है। मैं उद्योग विभाग का स्वयं विद्यार्थी हूँ। जहाँ तक उद्योगों को भूमि की उपलब्धता का प्रश्न है, उस संबंध में आप माहौल से अवगत हैं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण में जो प्रावधान रखे गये हैं, उन पर राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पायी है। जब तक इस राजनैतिक मुद्दे का हल नहीं हो जाता, राज्य सरकार का इसमें हाथ डालना संभव नहीं है। इसलिए Private Industrial Area को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि राजगीर में मेगा आई०टी० पार्क हेतु जमीन अधिगृहित की गयी है।

श्री शरण ने आगे कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए डी०एफ०आई०डी० से बात चल रही है और शीघ्र ही यह Operational हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को बैंकों का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। अगर बैंककर्मी कहीं से दोषी पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज होगी। अगर टास्क फोर्स ने किसी लोन को पास कर दिया है तो बिना किसी लिखित कारण बैंको को कोताही नहीं बरतनी चाहिए।

प्रधान सचिव ने कहा कि बिहार में नीतियों के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के संपर्क के संबंध में उन्होंने माहौल बनाने का सुझाव दिया और कहा कि आप अपनी समस्याओं को जितने प्रभावी तरीके से और बार-बार नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे तभी कुछ हो सकेगा। किसी मुद्दे को लेकर उद्योग जगत में आम सहमति नहीं बनेगी और माहौल नहीं बनेगा तब तक महत्वपूर्ण पहल संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्मार-पत्र में जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गये हैं उन्हें तीन माह के भीतर निबटारा कर लिया जाएगा। मेरी जिम्मेवारी होगी कि अपने कार्यकाल में नये उद्योगों को स्थापित नहीं कर पाया तो कम से कम जो स्थापित उद्योग हैं, उन्हें भरपूर सहयोग देंगे।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रेस बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

पटना में बनेगा वर्ल्ड क्लास आईटी टॉवर...

विजेन्द्र यादव
वित्त मंत्री, बिहार

सूबे के वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार सरकार का साल 2015-16 का बजट 12 मार्च 2015 को पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट बाजारवाद नहीं, बल्कि रोजगारवाद को बढ़ाने वाला है। पिछली योजनाओं को ही पूरा करने पर बजट में जोर दिया गया है। हालांकि ये साफ-साफ कहा गया है कि उच्च विकास दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे नीचे बनी हुई है।

बजट में विभागों को आवंटित राशियाँ

एजुकेशन : 22027.97 करोड़ रूपए देने की बात कही गई है। 2015-16 की भावी योजना के तहत शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के मद्देनजर सूबे मे संपन्न टोला सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की अर्हता रखने वाले अनाच्छादित 1896 बसावटों के लिए प्राथमिक विद्यालय का भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर स्थापित करना, राज्य के अर्हता रखने वाले अनाच्छादित बसावटों के लिए 610 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालय में उत्कमण, छात्र वर्ग कक्ष अनुपात को बेहतर करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 25,592 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम दो इकाई, बालक और बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय की उपलब्धता 15 अगस्त 2015 तक सुनिश्चित कराना प्रस्तावित है।

टोला के एक किमी पर प्राइमरी स्कूल : सूबे में पहली बार कराए गए टोला सर्वेक्षण के अनुसार 1896 ऐसे बसावट हैं, जहाँ मानक के अनुसार एक किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है वैसे बसावटों में विद्यालय के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

महादलित, अतिपिछड़ा व अल्पसंख्यक महिलाओं की साक्षरता पर दिया जोर : वित्तीय वर्ष 2015-16 में 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं और 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने एवं विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देने और 6 से 14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए सूबे में महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के संचालन का प्रस्ताव है।

निरक्षर बंदियों को बनाया जाएगा साक्षर : मुख्यमंत्री साक्षरता योजना के अंतर्गत सूर्ब के 57 काराओं में बंद निरक्षर बंदियों को साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से साक्षरता प्रदान किया जाएगा। इसमें लगभग 183.10 लाख रुपए खर्च होने का प्रस्ताव है।

एनर्जी : 8436.90 करोड़ रुपए बजट में देने की बात कही गई है। कहा गया कि नवम्बर 2013 में सूबे में पीक लोड पर लगभग 2000-2200 मेगावाट की आपूर्ति होती थी जो अक्टूबर 2014 में बढ़कर 2831 मेगावाट हो गयी है। सूबे के 11 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और शेष 27 जिलों में निविदा कार्य पूरा कर कार्य करने का आदेश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत 11 जिलों में 1000 सोलर पंप का कार्य प्रगति पर है और 733 सोलर पंप लगाए गए हैं।

वेलफेयर : 7951.40 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 2015-16 में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के 13800000 छात्र-छात्राओं को स्कूल स्कॉलरशिप देने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य योजना के अंतर्गत 161700 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। साल 2015-16 में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के अवशेष कार्यों के निर्माण एवं इसके संचालन के लिए 1500 लाख रुपए का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

सोशल वेलफेयर : 4179.20 करोड़ रूपए देने की बात कही गई है। राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677 आंगनबाड़ी केन्द्र/ मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। आहार का क्रय आंगनबाड़ी विकास समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2015-16 में राज्य योजना मद में योजना उद्वयय केन्द्रांश 50 परसेंट के लिए करीब 590 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राज्य के सभी जिलो में महिला विकास निगम के जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 250 लाख प्रस्तावित किया गया है।

रूरल डेवलपमेंट : रूरल डेवलपमेंट में 5216.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बीसी एंड एमबीसी वेलफेयर : 1975.30 रुपए का प्रावधान किया गया है। 2015-16 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के 13800000 छात्र-छात्राओं को स्कूल स्कॉलरशिप देने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य योजना के अंतर्गत 161700 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के अवशेष कार्यों के निर्माण एवं इसके संचालन के लिए 1500 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।

एससी एंड एसटी वेलफेयर : 1497.25 रुपए का प्रस्ताव किया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास के लिए चयनित संस्थाओं के माध्यम से 19 ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस मद में 220 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अंबेडकर फाउंडेशन बिहार की स्थापना की स्वीकृति के 2015-16 में 20 करोड़ रूपए प्रस्तावित किए गए है।

माइनारिटीज वेलफेयर : इस मद में 299.38 रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशालय का गठन कर निदेशक एवं कुछ अन्य पदाधिकारियों, कर्मियों का पदस्थापन भी कर दिया गया है। जिलों में 35 अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दी जा चुकी है। जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय भवन व विभाग के आवास भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

रूरल वर्क्स : इस मद में 6821.11 रुपए का प्रावधान किया गया है।

होम : इसमें 6179.05 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जेपी सेनानी सम्मान योजना में 2868 सेनानियों के पेंशन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल करीब 47 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं और वर्ष 2015-16 में 1330 लाख रुपए प्रस्तावित है।

रोड कंस्ट्रक्शन : इस मद में 5795.06 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। गंगा पथ, दीघा से दीदारगंज (3160.00 करोड़ रुपए) और पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर (1289.00 करोड) का निर्माण कार्य प्रगति में है। बख्तियारपुर-ताजपुर (1602.74 करोड़) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण, आरा मोहनियां पथ (एनएच 30) (रुपए- 1077.00 करोड़) में फोर लेनिंग का कार्य, रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर पथ (एनएच-31) (रुपए-1211.84 करोड़) में फोर लेनिंग का कार्य प्रगति पर है। जेआईसीए संपोषित योजना के अंतर्गत गया-हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहारशरीफ खंड (एनएच-82) का कार्य टेंडर प्रक्रिया में है।

हेल्थ : 4971.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 7 जनवरी 2015 में पेंटावैलेंट वैक्सीन को नियमित टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों व जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक-एक मॉड्यूलर ओटी की स्थापना की जाएगी। एनएमसीएच में जननी एवं शिशु के लिए 100 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल की स्थापना की जाएगी। आईजीआईएमएस का विकास मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा। सूबे के एक अस्पताल में आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट इकाई की स्थापना की जाएगी।

पंचायती राज : पंचायती राज हेतु 4364.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

एग्रीकल्चर : 2833.24 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। जलछाजन विकास के लिए दक्षिण बिहार के उपपठारी जिलों में निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिट्टी और जल संरक्षण के लिए चेक-डेम आदि का निर्माण किया जाएगा।

आईटी पार्क : पटना के बंदरबगीचा में बनेगा आईटी पार्क और वेलट्रॉन भवन में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना। आईटी डिपार्टमेंट के लिए 195.26 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। **(साभार : आइनेक्स्ट, 13.3.2015)**

बिहार बजट 2015-16 पर चैम्बर की प्रतिक्रिया

उत्तर और दक्षिण बिहार का सेतु नहीं बन पाया बजट : ओ० पी० साह

ओ० पी० साह
अध्यक्ष, बीसीसीआई

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 2015-16 के लिए पेश बिहार सरकार के बजट का स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने कहा है कि बजट में आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया है। इससे राज्य का आर्थिक विकास तेज होगा। अन्य प्रावधान भी सराहनीय हैं, लेकिन कुछ समस्याओं को बजट में जगह नहीं मिली है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। बजट में उद्योग विभाग के लिए गत वर्ष 452 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल 789 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुछ इसी तरह से राज्य के इस बजट में विद्युत के क्षेत्र में 2454 करोड़ की जगह 8414 करोड़, पथ निर्माण के क्षेत्र में 10190 करोड़ की जगह 11000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे आधारभूत संरचना में सुधार होगा। पटना-दीघा एलिवेटेड रोड के लिए 1289 करोड़ और विदुपुर गंगा ब्रिज के लिए भी आवंटन हुआ है।

गाँधी सेतु को नहीं मिली तवज्जो : बजट में प्राथमिकता के आधार पर महात्मा गाँधी सेतु को जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। इसकी स्थिति जर्जर है। उद्योगों की बेहतरी के लिए दीघा-सोनपुर रेल सह सड़क पुल व राजेन्द्र सेतु को शीघ्र चालू करने पर भी राज्य सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है। कुछ वस्तुओं पर प्रवेश कर की दर अब भी वैट की दरों के समकक्ष नहीं है। जबकि इसके बारे में सरकार का स्पष्ट आश्वासन है कि प्रवेश कर की दर वैट दरों के समकक्ष होनी चाहिए। इस पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था में उच्च विकास दर के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति अभी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे नीचे बनी हुई है। सरकार की कोशिश प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को देश के समानांतर लाना है।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.3.2015)

राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। ऋण जमा अनुपात 46 फीसद बताया गया है। यह भी स्वागत योग्य है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में निवेश बढ़ रहा है। **– सुभाष कुमार पटवारी**, उपाध्यक्ष, बीसीसीआई

बजट में प्राथमिकता के आधार पर महात्मा गाँधी सेतु को जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। इसकी स्थिति जर्जर है। **– मधुकर नाथ बरेरिया,** उपाध्यक्ष, बीसीसीआई

कुछ वस्तुओं पर प्रदेश कर की दर अब भी वैट की दरों के समकक्ष नहीं है। जबकि इसके बारे में सरकार का स्पष्ट आश्वासन है कि प्रवेश कर की दर वैट दरों के समकक्ष होनी चाहिए । इस पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। **– डॉ. रमेश गाँधी,** कोषाध्यक्ष, बीसीसीआई

उद्योग की बेहतरी के लिए दीघा-सोनपुर रेल सह सड़क पुल व राजेन्द्र सेतु को शीघ्र चालू करने पर भी राज्य सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है। ऐसा होने पर पटना का तो विकास होगा ही, इसका राज्य के विकास पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। **– ओ० पी० टिबड़ेवाल,** महामंत्री, बीसीसीआई

ऋण-जमा अनुपात 46 होना शुभ

राज्य में ऋण-जमा अनुपात 46 होना शुभ संकेत है। राज्य सरकार के प्रयासों से यह हो पाया है। आनेवाले दिनों में सरकार टैक्स फ्रेमवर्क में सुधार करेगी तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा और उद्योगों का और विकास होगा।

– पी० के० अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई
(साभार : दैनिक जागरण, 13.3.2015)

बिजली दर मे कमी पर चैम्बर ने किया स्वागत

ट्रांसमिशन व जेनरेशन के टैरिफ में कमी होने पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने स्वागत किया है। अध्यक्ष ने कहा कि कोयला व तेल के दाम में कमी आने पर इसके दर में कमी स्वाभाविक था। उम्मीद है कि घरेलू बिजली दरों में भी आयोग कमी करेगा। **(हिन्दुस्तान, 15.3.2015)**

विद्युत उत्पादन की लागत घटी फिर भी 3 फीसदी दर बढ़ाया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ.पी. साह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयला तथा तेल के दामों में कमी आने से विद्युत उत्पादन की लागत भी घटी है। ऐसी आशा की जा रही थी कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी दरें कम करेगी लेकिन आयोग ने 16.03.2015 को विद्युत दरों में तीन फीसदी की वृद्धि कर दी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.3.2015)**

सरकार ने रखी समावेशी विकास की नींव : राज्यपाल

राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने 11.3.2015 को विधान मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता एवं न्याय के साथ विकास का मूलमंत्र अपनाते हुए समावेशी विकास की नींव रखी।

सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम अपनाए और उसके मद्देनजर नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया जा रहा है। सरकार की न्याय के साथ विकास की नीति ने बिहार को न केवल उच्च विकास दर दिया, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है।

गिनाईं सरकार की उपलब्धियां : • अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण • राज्य में 93 हजार से अधिक अपराधियों को सजा • आतंकवाद पर काबू पाने को निरोधक दस्ता का गठन • राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा 3 फीसदी के अंदर • तकनीकी पदों पर बहाली के लिए आयोग का गठन • राज्य में 20 हजार 906 नए प्राथमिक विद्यालय खुले • विश्वविद्यालयों में 3345 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई • चिकित्सकों समेत बुनियादी सुविधाओं से लैस अस्पताल • सुपर स्पेशियिलिटी चिकित्सा व्यवस्था के ठोस कदम • 56 हजार किमी सड़कों, 14 हजार पुल पुलियों का निर्माण • मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना में 4,355 योजनाएं पूरी • बेली रोड व गांधी मैदान-चिरैयाटांड़ फ्लाईओवार निर्माण तेज • 8 हजार करोड़ की बिजली परियोजनाओं पर काम जारी • जिला मुख्यालयों में 22-24, ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली • बांका अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र को प्रस्ताव • कृषि के विकास के लिए दूसरा बहुआयामी कृषि रोड मैप बनाया • जैविक खेती के लिए 63 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना • वर्ष 2017 तक 24 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 12 करोड़ पौधे लगे • 33 करोड़ की लागत से समेकित बकरी-भेड़ योजना मंजूर • धान खरीद पर किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस • 12.32 अरब खर्च कर 3.26 करोड़ मानव दिवस का सृजन • दुर्गावती जलाशय योजना से 5900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई • चंदन नदी पर 94 किमी में तटबंट निर्माण कार्य अंतिम चरण में। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.3.2015)**

बिहार बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा

नीतीश सरकार ने अपने बजट में बिजली को एक बार फिर प्राथमिकता दी है। बजट में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ऊर्जा विभाग को 8436.89 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। इसमें बिजली की विभिन्न योजनाओं (योजना मद) पर 4058.60 करोड़ तो गैर योजना मद में 4378.29 करोड़ खर्च होंगे। बजट में मिले इस पैसे से बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा।

योजना मद के पैसे से बिजली की आधार भूत संरचनाओं को दुरुस्त किया जाएगा तो गैर योजना मद से जरूरत के अनुसार राज्य सरकार बिजली की खरीदारी करेगी। राज्य सरकार का अपना उत्पादन अभी शून्य है। इस वर्ष सरकार की अपनी इकाई बरौनी से 220 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ 500 मेगावाट की नई इकाई पर तेजी से काम हो सकेगा। एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम कांटी से 220 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू है। यहीं 195 मेगावाट की दो नई इकाइयों में एक सितम्बर 2015 तो दूसरी यूनिट जनवरी 2016 से बिजली उत्पादन शुरू हो सकता है। नवीनगर में 660 मेगावाट की तीन इकाई का निर्माण चल रहा है। चौसा, कचरा व पीरपैंती में 660 मेगावाट की छह इकाई पर काम चल रहा है। बांका में चार हजार मेगावाट की अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने जमीन व पानी चिह्नित कर प्रस्ताव भेज दिया है। सौ से अधिक आबादी वाले टोलों तक बिजली पहुंचाने की योजना 11 जिलों में चल रही है। बाकी 27 जिलों में प्रक्रिया शुरू है।

लागू होंगे कृषि रोडमैप के कार्यक्रम : वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। श्री विधि से धान तथा गेहूँ की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2015-16 में मक्का, दलहन व तेलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट व जैव उर्वरक के उत्पादन तथा उपयोग के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.3.2015)

वर्ष 2015 का बजट अनुमान एक नजर

कुल व्यय	120685.32	कुल प्राप्तियां	120914.40
गत वर्ष का बजट अनुमान	116886.16	राजस्व प्राप्तियां	103189.06
वर्ष 2014-15 से अधिक	3799.16	गत वर्ष राजस्व प्राप्तियां	101939.46
कुल गैर योजना व्यय	63529.59	राज्य के कर राजस्व	30875.00
गत वर्ष का गैर योजना	59231.04	राज्य के गैर कर राजस्व	3395.86
वर्ष 2014-15 से अधिक	4028.55	केन्द्र सरकार से प्राप्त कर	50747.58
कुल योजना व्यय	57425.73	केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान	18170.63
राज्य योजना	57137.62	पूंजीगत प्राप्तियां	17725.33
केन्द्रीय योजनागत योजना	288.11	(क) उधार	17708.81
गत वर्ष का राज्य योजना	57932.44	(कर्ज की वापसी)	16.52
वर्ष 2014-15 से कम	254.82	कुल व्यय	120685.32
राजस्व बचत	11980.95	(क) राजस्व व्यय	91208.11
(जीएसडीपी का 2.63 फीसदी)		(ख) पूंजीगत व्यय	29477.21
राजकोषीय घाटा	13584.46		
(जीएसडीपी का 2.98 फीसदी)			

नोट : सभी आंकड़े करोड़ रुपये में है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.3.2015)

उद्योग विभाग के बजट में 75% की वृद्धि, 789 करोड़ का प्रस्ताव

राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग के बजट में करीब 75 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। 12.03.2015 को वित्त मंत्री द्वारा सदन में पेश बजट में इस महकमे का बजट 452 करोड़ से बढ़ाकर 789 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इसमें योजना मद में 715 करोड़, जबकि गैर योजना मद में 73.62 करोड़ रुपए शामिल हैं।

बजट प्रस्ताव के मुताबिक उद्योगों को प्री-प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं के लिए 390 करोड़ रुपए, हस्तकरघा के लिए 30 लाख, भूअर्जन के लिए 20 लाख, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ और रेशम विकास के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा वर्ष 2014-15 तक कुल 369 बड़े उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इन इकाइयों में 3553.71 करोड़ का निवेश तथा संभावित नियोजन 15334 है। 1807 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश हो चुका है। 5 इकाइयों में उत्पादन शुरू है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 198 करोड़ रुपए राशि वैट की प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध कराई गई है। आधाभूत संरचना विकास प्राधिकार को जन निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। हस्तकरघा प्रक्षेत्र में बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं का मासिक 300 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए 5.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 329.96 लाख का ऋण वितरित किया गया है। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान केन्द्र में 5.53 लाख की लागत से एक बिक्री केन्द्र का निर्माण कराया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.3.2015)

आईटी पार्क और साइंस सिटी से संवरेगा पटना

बिहार बजट 2015-16

राजधानी पटना को सजाने-संवारने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस लिया है। 12.03.2015 को विधान सभा में वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कई घोषणाएं की। इसके तहत पटना के बंदर बगीचा में जहाँ आईटी पार्क बनाने की बात कही गई वही एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण को भी हरी झंडी मिली। सरकार ने इसके अलावा पहले की घोषित कई परियोजनाओं के लिए राशि का आवंटन भी किया।

3160 करोड़ से बनेगा दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ

सड़क : • कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा पर छह लेन पुल • मीठापुर आरओबी से स्टेशन होते हुए चिरैयाटांड उपरी पुल तथा एक्जिविशन रोड आर्म का गाँधी मैदान तक विस्तार • गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) • एम्स से दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर • बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पुल और पहुंच पथ • आरा-मोहनियां पथ को फोर लेन बनाना • रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर सड़क को फोरलेन बनाना

आईटी : • पटना के बंदर बगीचा में आईटी पार्क की स्थापना • पटना में स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना • आईआईटी में आईटी इनकंबेशन सेन्टर, डाक बांगला के पास विश्वस्तरीय आईटी टावर • बिस्कोमान स्थित साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क को अपग्रेड करना।

नगर विकास : • पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए एसपीवी का गठन • शहरी आवास योजना के तहत पटना की तीन योजनाओं समेत सात के लिए 12 करोड़ रुपये।

स्थास्थ्य : • आईजीआईएमएस में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना • नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जननी एवं शिशु के लिए सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल।

विज्ञान-प्रावैधिकी : पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी का निर्माण।

बिजली : नगर निगम के परम्परागत स्ट्रीट लाईट को बदलकर 366 एलईडी लाईट लगाना।

वन एवं पर्यावरण : पटना शहर में वृक्षारोपण, बंजर और जलजमाव वाले क्षेत्र में दस लाख पौधारोपण।

भवन निर्माण : • पटना में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह ज्ञान केन्द्र का निर्माण • विधानसभा भवन व सचिवालय विस्तारीकरण के कार्य को 362 करोड़ • पटना हाई कोर्ट के विस्तारीकरण को 116 करोड़।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.3.2015)

कहाँ खड़े हैं हम

आर्थिक सर्वेक्षण (2014-15) ने बदलते बिहार की तस्वीर पेश की है। बिहार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च बढ़ा है, लेकिन कई मोर्चों पर अब भी चुनौतियाँ हैं-

1. आत्मनिर्भरता की राह पर बिजली : • **उपलब्धता** 3500 मेगावाट मांग रही 14-15 में, 2831 मेगावाट **उपलब्धता,** 669 मेगावाट अन्तर • 2013-14 से 3000 मेगावाट की मांग थी • **उपलब्धता** 2335 मेगावाट थी।

2. मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था (वित्तीय स्थिति) : • 10.4% वार्षिक दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था 2010-11 से 13-14 के बीच • 33954 रुपये है बिहार में प्रति व्यक्ति की आय • 2013-14 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय का औसत (देश के) बढ़कर 39.22 फीसदी हो गया।

3. उत्पादन बढ़ा, सिंचाई चुनौती (सिंचाई/कृषि) : • 117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है बिहार की सिंचाई क्षमता • 67.21 लाख हेक्टेयर ही है वर्त्तमान सिंचाई की सृजित क्षमता • 59.20 लाख हेक्टेयर क्षमता का ही राज्य में उपयोग हो रहा है।

4. सड़क बनने की रफ्तार बढ़ी (सड़क/ पुल) : • 2262244.58 किमी है बिहार में सड़कों की कुल लम्बाई • 4320.99 किमी है 2014 में राज्य में एनएच

की लम्बाई • 28% की बढ़ोत्तरी हुई ग्रामीण सड़कों की लम्बाई में 2014 में, 2013 में यह आंकड़ा 1.62 लाख किमी था जो 2014 में 2.07 लाख हो गया है।

5. सुधरने लगी सेहत (स्वास्थ्य) : • 11464 रोगियों का इलाज हुआ 2013 में सरकारी अस्पतालों में • 3077 रोगी ही उपचार पाते थे 2007 तक सरकारी अस्पतालों में।

6. विकास पर खर्च 29% बढ़ा (महिला सशक्तीकरण) : • 36 जिलों में चल रहे महिलाओं के लिए हेल्पलाइन • **बदलाव** 2013-14 में 66912 एसएचजी का गठन • 57.55 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण।

7. लगाना होगा और जोर (गरीबी उन्मूलन) : • 133.82 लाख जॉब कॉर्ड बने 2011-12 में • 131.87 लाख जॉब कॉर्ड बनाये गये 2013-14 में। **चुनौतियाँ:** राज्य में 14 लाख है गरीब परिवार, सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण गरीबों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती।

8. नामांकन में लड़कियाँ आगे (शिक्षा) : • 74.77 लाख थी 2012-13 में लड़कियों का नामांकन। **बदलाव :** प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2006-07 से 2012-13 के बीच ड्राप आउट रेट में 14.4% की कमी आई है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 12.3.2015)

बिजली कंपनी घाटा कम करे, लोगों पर बोझ न डाले

बिजली दर में 2.5% वृद्धि के साथ ही बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी को घाटा कम करने की नसीहत भी दी है। खासकर संचरण- वितरण (तकनीकी व व्यावसायिक) नुकसान कम करने को कहा है। कंपनी अगर इस घाटे को कम करने में विफल रही तो आगे के वर्षों में उसे खामियाजा भुगतना होगा।

ग्रिड से लोगों के घरों तक पहुंचने वाली बिजली का नुकसान **ट्रांसमिशन लॉस** होता है। बिजली चोरी, मीटर रीडिंग का नहीं होना, बिल भुगतान न होना **डिस्ट्रीब्यूशन लॉस** है। 2014-15 में आयोग ने इस नुकसान को 21.40 फीसदी पर लाने का टास्क दिया था। लेकिन दक्षिण बिहार में 46.65 फीसदी तो नार्थ बिहार में 31.48 फीसदी (कुल 39.06 फीसदी) नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आयोग ने इस नुकसान को 20 फीसदी पर लाने का टास्क दिया है, जबकि कंपनी ने 35.06 फीसदी का नुकसान होने का अनुमान लगाया है।

राज्यों का टैरिफ

राज्य	न्यूनतम	अधिकतम
बिहार	2.10	5.45
उत्तर प्रदेश	4.00	5.50
उत्तराखंड	2.30	3.50
झारखंड	2.40	3.00
पश्चिम बंगाल	4.12	7.95
नई दिल्ली	4.00	8.75

बिहार में अब भी सस्ती बिजली : गांव में 10 पैसे व शहरी इलाके में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि के बावजूद अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। बिहार से सटे झारखंड में 2.40 रुपए प्रति यूनिट बिजली है तो पश्चिम बंगाल में न्यूनतम 4.12 रुपए यूनिट बिजली बिल देना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम चार रुपए यूनिट है।

बिजली टैरिफ रेट

शहरी क्षेत्र (घरेलू)

यूनिट	अभी	एक अप्रैल से
1-100	2.85	रु. 3.00 प्रति यूनिट
101-200	3.50	रु. 3.65 ,,
201-300	4.20	रु. 4.35 ,,
300 से अधिक	5.30	रु. 5.45 ,,

ग्रामीण इलाका (घरेलू)

यूनिट	अभी	एक अप्रैल से
0-50	2.00	रु 2.10 प्रति यूनिट
51-100	2.30	रु. 2.40 ,,
100 से ऊपर	2.70	रु. 2.80 ,,
बिना मीटर के	160	रु. 170 फिक्स्ड

उद्योग

एलटीएस-एक	5.35	5.50 प्रति यूनिट
एलटीएस-दो	5.70	5.85 ,,
एचटीएस-एक	5.70	5.85 ,,
एचटीएस-दो	5.50	5.65 ,,
एचटीएसएस-तीन	5.40	5.55 ,,
एचटीएसएस	3.10	3.25 ,,

(एलटीएस-लो टेंशन इंडस्ट्रियल, एचटीएस-हाई टेंशन सप्लाई)

खेती

ग्रामीण	रु. 120	रु. 120 प्रति हॉर्सपावर
शहरी	रु. 160	रु. 160 प्रति हॉर्सपावर
कुटीर ज्योति	रु. 55	रु. 60 महीना

"बिजली कंपनी ने टैरिफ में 20.66 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग के फैसले में मात्र ढाई फीसदी वृद्धि की गई जो काफी कम है। आयोग के फैसले की समीक्षा होगी और जरूरत हुई तो केंद्रीय आयोग में अपील भी की जा सकती है।

– **आर लक्ष्मणन**, प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.3.2015)

11 जिलों के सभी गांवों में छह माह में बिजली

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सौ की आबादी वाले टोलों तक बिजली पहुँचाने का काम 2012 से चल रहा है। नार्थ बिहार के चार जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज व सीवान तो दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधीन सात जिले बांका, भोजपुर, नालंदा, नवादा, पटना रोहतास व गया के 100 से अधिक आबादी वाले टोलों में बिजली पहुँचाई जा रही है। इस साल तक बिजली में सुधार का दावा कर चुकी सरकार ने इस योजना को समय पर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

सख्ती : • बिजली पहुँचाने के लिए कंपनी ने एजेंसियों को दिया अल्टीमेटम • उत्तर बिहार के 4 व दक्षिण बिहार के 7 जिलों में चल रही योजना 11 जिले में बिजली पहुँचाने वाली योजना की स्थिति।

काम	लक्ष्य	स्थिति	बांकी
वैसे गाँव जहाँ बिजली नहीं है	1338	278	1060
वैसे गाँव जहाँ आंशिक बिजली है	12790	1692	11098
बीपीएल परिवार को बिजली	2898328	162973	2735355
सब-स्टेशन	36	00	36
राशि (करोड़ में)	2994.11	963.91	2030.2

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.3.2015)

उद्यमियों को परेशान किया तो प्राथमिकी

बैंक यदि अकारण उद्यमियों के आवेदन लौटाते हैं या उन्हें बेवजह ऋण के लिए दौड़ाते हैं तो उद्योग विभाग ऐसे बैंकों पर एफआईआर दर्ज करेगा। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने 10.03.2015 को विभागीय अधिकारियों को उद्यमियों को परेशान करने वाले बैंकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधकों की बैठक में मंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति पर चिंता जताई। निर्देश दिया कि उद्यमियों के आवेदन का निपटारा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 15 दिनों में करें। श्री रजक ने मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना के तहत क्लस्टर सेंटरों को और प्रभावी बनाने को कहा। बैठक में प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण, शैलेश ठाकुर समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.3.2015)

कम बिजली उपभोग करने पर होगी जाँच

कम बिजली उपभोग करने वालों के घर पहुँचकर विद्युत कंपनी के अभियंताओं ने मीटर निरीक्षण शुरू किया है। विद्युत कंपनी उपभोक्ताओं के लोड और यूनिट का मिलान करा रही है। बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान के साथ ही पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान (पेसू) ने बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने का अभियान भी छेड़ दिया है। विद्युत कंपनी की तरफ से पेसू अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के यहाँ बकाया है तो बिजली कनेक्शन काट दें।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.3.2015)

आर्थिक सर्वेक्षण

बिहार ने दूरसंचार के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। सूबे में वाहनों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है।

• राज्य में टेलीफोन (मोबाइल समेत) कनेक्शनों की संख्या 6 करोड़ 3 लाख हो गयी है। सिर्फ मोबाइल कनेक्शनधारी 6 करोड़ 48 हजार है। इनमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी 96 फीसदी है। पिछले साल यह संख्या समेकित रूप से 5.47 लाख था। • राज्य में डाकघरों की संख्या 9030 थे। इनमें 90 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

राज्य में 6 रात्रिकालीन डाकघर है। • राज्य में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या वर्ष 2008-09 के 2.20 लाख से बढ़कर 2013-14 में 5.54 लाख हो गयी। वर्ष 2014-15 के छह माह में 2.96 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। • इस अवधि में ट्रकों व टैक्सियों की संख्या में तीन गुनी जबकि आटो-रिक्शा की संख्या में चार गुनी वृद्धि हुई।

औद्योगिक क्षेत्र : सकल घरेलू उत्पाद में 18.4 फीसदी योगदान रहा

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा रहा है। वर्ष 2012-13 में योगदान 18.1 और 2013-14 में 18.4 फीसदी रहा। हालांकि यह वर्ष 2011-2012 की तुलना में कम है। 2006-07 में राज्य में कुल 1.63 लाख मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत थी वहीं 2013-14 में बढ़ कर यह 1.98 लाख हो गई। इन वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास की गति 21.4 फीसदी रही है। राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और 7 पयर्टन सर्कल की पहचान की गई है। इन सर्कल में आनें वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2013 में 2.24 करोड़ पर्यटक आए। सितम्बर 2014 तक निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 1891 प्रस्ताव को यूनिट लगाने की अनुमति दी है और अनुमान है राज्य में 2.88 लाख करोड़ का निवेश होगा। कांफेड द्वारा दूध संग्रहण में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2007-08 में जहाँ 4.79 लाख किलोग्राम दूध का संग्राहण होता था वहीं 2013-14 में बढ़कर यह 14.94 लाख किलोग्राम पर पहुँच गया है।

कर राजस्व : 25% की दर से बढ़ोतरी, 42 फीसदी हिस्सा बिक्री कर का

राज्य के कर राजस्व में 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2009-10 में कर राजस्व 8090 करोड़ था, जो कि 2013-14 में 19961 करोड़ रुपए हो गया। राज्य के कुल राजस्व में 42 फीसदी हिस्सा बिक्री कर का है। माल एवं यात्री कर से 22%, राज्य उत्पाद शुल्क से 16%, स्टांप एवं निबंधन शुल्क 14% और वाहन करों से 4% प्राप्त होता है। हालांकि नन टैक्स राजस्व में इस दौरान 1970 करोड़ रुपए से कम होकर 1545 करोड़ रुपया हो गया। वर्ष 2012-13 में राजस्व अधिशेष 5101 करोड़ रुपया था जो कि 2013-14 में बढ़कर 6442 करोड़ रुपया हो गया। राज्य के कर राजस्व में वृद्धि में केंद्रीय करों में राज्य का 44 फीसदी हिस्सा बढने और अपने राजस्व में 56 फीसदी बढोतरी होने के कारण हुई हैं। राज्य का विकासमूलक राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 के 20274 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2013-14 में बढ़कर 40455 करोड़ होगा। जबकि इस दौरान पूंजीगत परिव्यय 14001 करोड़ में 10811 करोड़ रुपए का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया। वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय में 8011 करोड़ रुपए की बढोतरी हुई जिसमें सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 3288 करोड़ यानी 41 फीसदी, आर्थिक सेवाओं का 1350 करोड़ और सामान्य सेवाओं का हिस्सा 3373 करोड़ यानी 42 फीसदी रहा है।

साख-जमा अनुपात : बैंकों में बढ़े पैसे, मगर लोन वितरण में आई कमी

9वें वार्षिक सर्वे में राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों को उनके उदासीन रवैये का आईना दिखाया गया है। सर्वेक्षण में बैंक में बढ़ते जमा की तुलना में अपेक्षित ऋण नहीं देने का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय साख-जमा अनुपात 78% की तुलना में राज्य का अनुपात 46.51% है। रोचक यह है कि आर्थिक सर्वे और राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति (एसएलबीसी) की बैठक में वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़े अलग कहानी बयां करते हैं। बैठक में जो आंकड़े वित्त विभाग ने उपलब्ध कराए हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य का साख जमा अनुपात 42.89% दिखाया गया है जबकि आर्थिक सर्वे में यह अनुपात 46.51% दिखाया गया है।

साख-जमा का अनुपात

वर्ष	आर्थिक सर्वे	एसएलबीसी	वर्ष	आर्थिक सर्वे	एसएलबीसी
2010-11	33.99	33.99	2013-14	46.51	42.89
2011-12	36.70	36.70	2014-15	45.74 (सि.14)	42.14 (दि.14)
2012-13	40.59	38.68			

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.3.2015)

सूबे में ऑनलाइन सामान मंगवाना पड़ेगा महंगा

बिहार में ऑनलाइन सामान खरीदना महंगा पड़ सकता है। वजह यह है कि बिहार में ऑनलाइन सामान की खरीद पर इंट्री टैक्स लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि बिहार बजट में इस संबंध में घोषणा हो सकती है।

बताया जाता है कि घोषणा होने के बाद वाणिज्य कर विभाग के नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद सामान मंगवाने वाले कुरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनियों को वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वह सामान की डिलीवरी से पहले ग्राहकों से विभाग द्वारा निर्धारित इंट्री टैक्स वसूल करेगी। उसे कुरियर या ट्रांसपोर्ट कंपनी विभाग में जमा करेगी। वाणिज्य कर विभाग सामान के आधार पर 4, 8,12 व 16 प्रतिशत इंट्री टैक्स वसूल करता है।

राजस्व की प्राप्ति : विभाग का मानना है कि ऑनलाइन सामान के इंट्री टैक्स से लगभग 3000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.3.2015)

इंटरनेट बैंकिंग में छोटी भूल पड़ सकती है महंगी

इंटरनेट बैंकिग (ई-बैंकिंग) के जरिये पैसा भेजना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। लेकिन इसमें गलत खाता संख्या लिख देने की वजह से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा जाने का भी खतरा बरकरार है। ऐसा होने पर उसकी वसूली बेहद मुश्किल है। ऐसे में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) को लेकर सवाल उठने लगे हैं जिसके जरिए ई-बैंकिग होती है। निजी क्षेत्र के बैंक के उपभोक्ता इसका शिकार हो चुके हैं।

बरतें सावधानी

क्या हैं निर्देश : ई-बैंकिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश दे रखा है कि जिस व्यक्ति को पैसा भेजा जा रहा है उसका खाता संख्या सहित अन्य तथ्यों का मिलान करना बैंकों की जिम्मेदारी है। हालांकि, इसके बाद भी बैंक केवल खाता संख्या को तरजीह देते हैं जिसकी वजह से कई बार गलती पकड़ में नहीं आती है।

ई-बैंकिंग की तेज रफ्तार : भारत में ई-बैंकिग सालाना कारोबार 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और यह 40 फीसदी के तेजी से बढ़ रहा है। इसमें नेट बैंकिग की करीब 40 फीसदी, डेबिट कार्ड की करीब 30 फीसदी, क्रेडिट कार्ड की करीब 20 फीसदी और अन्य की 10 फीसदी हिस्सेदारी है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.3.15)

'कर्ज सस्ता करें बैंक'

बैंक प्रमुखों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी सलाह

डूबते कर्ज पर बैंकों को राहत : रिजर्व बैंक ने बैंकों को डूबे कर्ज (एनपीए) की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को अपने लाभ एवं हानि खाते में लौटाने की अनुमति दे दी है, बशर्ते यह बिक्री 26 फरवरी, 2014 से पहले की गई हो। केन्द्रीय बैंक ने 3 फरवरी को कहा था कि वह इस मोर्चे पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करेगा।

सात बैंक जुटा सकेंगे धन : वित्त मंत्रालय ने सात सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को बाजार से धन जुटाने की अनुमति दे दी है। बैंक इस राशि का इस्तेमाल अपनी विस्तार योजनाओं के साथ-साथ वैश्विक पूंजी पर्याप्तता नियमों के पालन के लिए करेंगे।

आंकड़ों पर एक नजर : • 0.50 फीसदी नीतिगत दर घटा चुका है रिजर्व बैंक वर्ष 2015 में अब तक • 04 मार्च को 0.25 फीसदी कम किया था रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर • 0.25 फीसदी नीतिगत दर में कटौती की थी रिजर्व बैंक ने जनवरी में • 07 अप्रैल को आगामी मौट्रिक नीति की समीक्षा करेगा रिजर्व बैंक

व्यावसायिक फैसले बिना भय के करें : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय स्वायत्ता का वादा करते हुए मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से व्यावसायिक फैसले बिना भय और पक्षपात के लेने को कहा है। इसी के साथ उन्होंने सभी बैंकों को सलाह दी कि वे ऋण का उचित विस्तार करें जिससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कायम रखा जा सके। (साभार : हिन्दुस्तान 12.03.2015)

सबसे सस्ते इंश्योरेंस के लिए खाता, आधार जरूरी

वित्त मंत्रालय ने 12 रुपए में दुर्घटना बीमा और 330 रुपए में जीवन बीमा कवर देने के नियम तय कर दिए हैं। पॉलिसी लेने के लिए बैंक खाता और उससे जुड़ा आधार नंबर जरूरी होगा। दोनों में बीमा कवर दो लाख रुपए का मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

• **कौन ले सकता है पॉलिसी :** 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति। आधार कार्ड और उससे जुड़ा बैंक खाता जरूरी

• **स्कीम से कैसे जुड़ेंगे :** 1 जून तक फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना होगा। हर साल पॉलिसी रिन्यू करानी होगी • **रिस्क कवरेज :** हादसे में मौत /पूर्ण विकलांग हुए तो 2 लाख, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का कवर • **कैसे देंगे प्रीमियम :** बीमाधारक के खाते से कटेगा। बैंक की कई साल की पॉलिसी एकमुश्त भी दे सकते हैं • **कौन सी कंपनी चलाएगी :** ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस। निजी कंपनियां भी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

• **कौन ले सकता है पॉलिसी :** 18 से 50 साल का व्यक्ति। 50 की उम्र से पहले पॉलिसी लेने पर 55 तक जारी रहेगी • **स्कीम से कैसे जुड़ेंगे :** हर साल पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। इसके लिए कोई एक तारीख तय नहीं की गई है • **रिस्क कवरेज :** किसी भी वजह से बीमाधारक की मौत होने पर आश्रित को दो लाख का कवर मिलेगा • **कैसे देंगे प्रीमियम :** बैंक खाते से हर साल कटेगा। 1साल से ज्यादा का प्रीमियम एकमुश्त भी कटवा सकते हैं • **कौन सी कंपनी चलाएगी :** एलआईसी यह स्कीम चलाएगी। निजी जीवन बीमा कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.3.2015)

भारत सरकार

Government of India

कार्यालय, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पटना

Office of the Principal Chief Commissioner of INCOME TAX, Patna

केन्द्रीय राजस्व भवन, प्रथम तल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–1

1st FLOOR, CENTRAL REVENUE BUILDING, BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-1

Phone : EPABX- 0612-2504020-22,24,25,2500580-83

सर्वसाधारण हेतु सूचना

आयकर विभाग द्वारा खुले एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के **माननीय प्रधानमंत्री जी** के **'सुशासन दिवस'** के वादे के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार एवं झारखण्ड स्थित आयकर विभाग के सभी कार्यालय जनता की शिकायतों को सुनने एवं दूर करने की कोशिश हेतु **प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को 10: 00 बजे पूर्वा० से 01.00 बजे अप०** तक **"जनता मुलाकात दिवस"** के रूप में मनाएंगे। उपरोक्त दिवस एवं अवधि में सर्वसाधारण बिना किसी पूर्व अनुमति के आयकर विभाग के अधिकारियों से मिल सकेंगे।

लोकहित में जारी

द्वारा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
(बिहार एवं झारखण्ड), पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.3.2015)

सर्किल दरों के लिए नई श्रेणी

बिहार सरकार जमीन की ऊँची दरों से जुझ रहे निवेशकों को देगी राहत

बिहार सरकार जमीन की ऊँची दरों की समस्या से जूझ रहे निवेशकों को राहत देने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार अब सर्किल दरों के निर्धारण के लिए एक नई श्रेणी बना रही है, जिसके तहत औद्योगिक इकाइयों के लिए दरें कम रखी जाएंगी।

• राज्य सरकार सर्किल दरों के निर्धारण के लिए अब औद्योगिक भूमि के नाम से बनाएगी एक नई श्रेणी • बिहार में इस समय सर्किल दरें निर्धारित करने की दो श्रेणियाँ–कृषि और वाणिज्यिक–हैं • बिहार में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सर्किल दरें काफी अधिक • जमीन उपलब्ध नहीं होने से ज्यादातर निवेश प्रस्ताव नहीं उतर रहे जमीन पर।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.3.2015)

कार्ड के बिना भी कैश

एटीएम से आसानी से निकाल सकेंगे

क्या आप जानते हैं कि बैंक में यदि आपका खाता नहीं हैं या फिर आपके पास डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड नहीं है, तब भी आप एटीएम से रकम निकाल सकते हैं? जी हां! अब यदि कोई आपको रकम भेजेगा, तो आप किसी कार्ड के प्रयोग के बिना भी एटीएम से रुपये निकाल सकते हैं। बैंकों ने इसके लिए कार्डलेस कैश सिस्टम शुरू किया है। जिसके माध्यम से बिना कार्ड के रकम निकाली जा सकती है। किसी को भेजी जा सकती है या कहीं से रकम हासिल की जा सकती है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.3.2015)

खाद्य विभाग नहीं बना रहा लाइसेंस

देश समेत प्रदेश में हर खाद्य सामग्री में धड़ल्ले से हो रही मिलावटखोरी की रोकथाम को लाइसेंस व पंजीयन का नियम बनाया गया है। खाद्य सामग्री के क्रय–विक्रय का कारोबार करने के लिए लाइसेंस या उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। हालांकि, गत एक माह से पटना समेत तीन प्रमंडल में लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। एक ओर कुछ लोग लाइसेंस न होने से कारोबार नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग बिना लाइसेंस ही व्यापार कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीनों प्रमंडलों में लाइसेंस देने के लिए सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं।

क्या है मामला : खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने को केंद्र सरकार की पहल पर अक्टूबर 2011 में खाद्य संरक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग से अलग किया गया है। उस समय वरिष्ठता के आधार पर 9 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को लाइसेंस जारी करने के लिए अभिहित पदाधिकारी बनाया गया था।

इसके अलावा प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण व 25 लाख से कम टर्नओवर वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयत करने के लिए 14 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त थे। छह अभिहित पदाधिकारी अब तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि एक विगत दो वर्षों से निलंबित चल रहे हैं। कार्यरत दो लाइसेंसिग पदाधिकारियों को छह प्रमंडल में लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.3.2015)**

जल परिवहन के लिए वाराणसी से हल्दिया तक तैयार होगा चैनल

जल परिवहन में असीम संभावनाओं को देखते हुए नदियों में ड्रेजिंग कराने व यातायात की सुविधा बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वाराणसी से लेकर हल्दिया तक चैनल मेंटेन किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अभियांताओं व इससे जुड़े अधिकारियों को ड्रेजिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। ये बातें आइडब्ल्यूएआई के चेयरमैन अमिताभ वर्मा ने गायघाट स्थित राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान की ओर से ड्रेजिंग व टायप ऑफ ड्रेजर्स पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं। जल संसाधन विभाग के सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि नदियाँ प्रोपर चैनल में रहे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोसी, गंडक व सोन सहित इसके संपर्क की नदियों में बेहतर यातायात व्यवस्था को लेकर कार्य किया जा रहा है कोसी बराज व कोसी महासेतु से पायलट चैनल निकाले जाने की योजना है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 14.3.2015)**

डीपीआर से एक स्टेशन आगे बढ़ी मेट्रो

बजट 2015–16 में पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 2169. 85 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा–राजधानी को संवारने के लिए धन की कमी नहीं होगी। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट की कागजी कार्रवाई पूरी कर कंपनी राइट्स ने प्रस्ताव नगर विकास विभाग को सौंप दिया है। मेट्रो प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर पूरा होगा। सरकार ने वर्ष 2021 तक मेट्रो रेल के पहले फेज का काम पूरा करने का निर्णय लिया है। नगर विकास विभाग इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजेगा।

राजधानी के सभी प्रमुख क्षेत्रों में मेट्रो की पहुंच होगी। एम्स से लेकर पटना सिटी व दीदारगंज तक, दानापुर से लेकर पटना हाईकोर्ट व स्टेशन तक मेट्रो रेल दौड़ेगी। गंगा एक्सप्रेस वे के एक छोर दीघा से हाईकोर्ट तक मेट्रो रेल का संपर्क बनेगा।

पहले फेज का पहला चरण

कॉरिडोर 1–ए : दानापुर से मीठापुर बाइपास चौक वाया हाइकोर्ट व पठना रेलवे स्टेशन तक साढ़े 14 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछेगी। दानापुर से आरपीएस मोड़ तक ओवर ग्राउंड मेट्रो रेल चलेगी आरपीएस मोड़ से पटना रेलवे स्टेशन तक अंडर ग्राउंड तथा पटना रेलवे स्टेशन से बाइपास चौक तक ओवर ग्राउंड • **कॉरिडोर–बी** के तहत दीघा–हाईकोर्ट लिंक (5.5 किलोमीटर) • **कॉरिडोर–1 ए** के हाईकोर्ट से मिलेगा तथा आगे वाया पटना रेलवे स्टेशन मीठापुर तक जाएगा।

कॉरिडोर–2 : दीघा से शिवपुरी तक रेलवे लाइन के किनारे ओवर ग्राउंड फिर आगे हाईकोर्ट तक अंडरग्राउंड रेल चलेगी। पटना रेलवे स्टेशन, डाकबंगला चौक से प्रस्तावित अंतराज्यीय बस पड़ाव (आइएसबीटी) वाया गांधी मैदान, मेडिकल कॉलेज, राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन, अगमकुआं, गांधी सेतु तक 16 किलोमीटर रेल

लाइन बिछेगी। पटना रेलवे स्टेशने से राजेन्द्र नगर तक अंडरग्राउंड और आगे प्रस्तावित अंतरराज्यीय बस पड़ाव (आइएसबीटी) तक ओवर ग्राउंड रेल चलेगी।

कॉरिडोर-3 : बाइपास चौक, मीठापुर से दीदारगंज वाया ट्रांसपोर्ट नगर एनएच-30 बाइपास के साथ-साथ रेल लाइन बनेगी, जो 13 किलोमीटर लंबी होगी।

दूसरा चरण

कॉरिडोर-चार : बाइपास रोड के साथ-साथ ओवर ग्राउंड रेल चलेगी। बाइपास चौक, मीठापुर से फुलवारीशरीफ, एम्स वाया अनीसाबाद साथ-साथ एनएच 30 बाइपास तक 11 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी। बाइपास रोड के साथ-साथ ओवर ग्राउंड मेट्रो रेल परिचालन का प्रस्ताव है • 03 लाख लोग पहले फेज का काम पूरा होने पर मेट्रो से सफर कर सकेंगे • 450 करोड़ प्रति किमी भूमिगत मेट्रो रेल के निर्माण पर खर्च होगा •200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है प्रति किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो रेल पर। (साभार : दैनिक भास्कर, 13.3.2015)

मरीन ड्राइव की तर्ज पर बख्तियारपुर तक बनेगा गंगा पथ

बजट में गंगा पथ के लिए 3160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले फेज में दीघा से दीदारगंज को जोड़ने वाली करीब साढ़े 21 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का काम मरीन ड्राइव की तर्ज पर शुरू हो गया है। फेज-2 में इसे बख्तियारपुर तक ले जाने की योजना है। वहाँ इसे बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा पर बन रहे पुल से जोड़ा जाएगा। इसके पहले कच्ची दरगाह में गंगा पथ पर प्रस्तावित छह लेन वाले पुल को भी इस सड़क से जोड़ा जाएगा। इस सड़क के निर्माण के साथ ही हाइकोर्ट के निर्देश के बाद गंगा को भी पटना के निकट लाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इससे गंगा पथ दर्शनीय स्थल के रूप में भी विकसित होगा।

शहर के ट्रैफिक लोड को कम करेगी सड़क

साढ़े 21 किमी लंबी फोर लेन सड़क पटना शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगी। एनएच-19, एनएच 30, एनएच 77 व एनएच-98 से भी यह सड़क जुड़ेगी। भू-अर्जन सहित 3160 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से राजधानी का ट्रैफिक लोड कम होगा। अशोक राजपथ में इसे पांच जगहों पर निकास व प्रवेश देने का प्रस्ताव है। फेज-। में दीघा घाट से शुरू होकर दीदागंज में यह सड़क एनएच-30 के जंक्शन के समीप समाप्त होगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 13.3.2015)

RAILWAY POLICE TO ACCEPT 'ZERO FIR ' ABOARD RUNNING TRAINS

Passengers on board trains could lodge complaints regarding their missing / stolen belongings or any other problems they encounter midway to the beat constables on escort duty.

Upon obtaining the complaint, GRP personnel on board would hand over a receipt to passenger concerned, affixing his own signature as well as taking the traveller's signature.

(Details : Hindustan Times , 14.3.2015)

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर टोल टैक्स 1 अप्रैल से

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर पहली अप्रैल से लगेगा टोल टैक्स। पिछले वर्ष सितंबर में ही यह फोरलेन सड़क बनकर तैयार हो गया था। टोल प्लाजा को स्थानांतरित किए चाने का मामला न्यायालय में चले जाने के बाद मामला अटक गया था। गुरुवार को कोर्ट से टोल टैक्स के पक्ष में आए फैसले के बाद निर्माण कंपनी ने शुक्रवार को इस बारे में एनएचएआई की सूचित कर दिया है कि इस सड़क पर पहली अप्रैल से टोल टैक्स लिया जाएगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 14.3.2015)

बस एक क्लिक पर घर बैठे ही होगी आपके मकान की रजिस्ट्री

राज्य में जल्द ही रजिस्ट्रेशन की सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत होने जा रही हैं। जमीन रजिस्ट्री से लेकर तमाम तरह की निबंधन प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इसके लिए लोग चालान से लेकर रजिस्ट्री फीस तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा पहले चरण में पटना के आसपास स्थित निबंधन कार्यालय दानापुर, मसौढ़ी और फुलवारीशरीफ में बहाल की जायेगी। ऑनलाइन का काम मार्च के अंत तक शुरू कर दिया जायेगा। इसके बाद बाकी जिलों में मई तक में इसे लागू कर दिये जाने की उम्मीद है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को पूरी तरह से पब्लिक फ्रेंडली बनाने की तैयार की जा रही है।

दलालों से मिलेगी मुक्ति : • कम समय में काम हो जायेगा। • बिचौलियों का नहीं चलेगा। • ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। • फर्जीवाड़े की आशंका खत्म हो जायेगी। • रजिस्ट्री की सही दर की जानकारी मिल जायेगी। • अन्य दरों में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। • व्यक्ति खुद से भी पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.3.2015)

बधाई

विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्य डॉ० अजय कुमार सिंह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। चैम्बर की ओर से डॉ० अजय कुमार सिंह को हार्दिक बधाई।

सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही नारी

कार्यक्रम में उपस्थित आधार महिला की अध्यक्ष डॉ० गीता जैन (बाँयें से दूसरी)। उनकी बाँयीं ओर आधार महिला की सचिव श्रीमती गीता रानी, सुश्री माधबी सेन गुप्ता एवं उनकी दाँयीं ओर सुश्री ममता सिन्हा।

आज की नारी कमजोर नहीं है। अपने उल्लेखनीय कार्यों से हर क्षेत्र में कामयाबी का कीर्तिमान बना रही है। जरूरत है शुरूआती दौर से ही सही शिक्षा और रोजगार के लिए प्ररित करने की। 9.3.2015 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉसर्म एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा स्थापित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में वक्ताओं ने ये बातें कहीं।

मौका था आधार महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का। कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौशल विकास उपसमिति के चेयरमैन मुकेश जैन ने कहा कि अपने अदुभुत साहस, परिश्रम व बुद्धिमता के आधार पर महिलाएं विश्वपटल पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं को कई तरह के नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बना रहा है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्था की सचिव गीता रानी ने कहा कि यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक तरक्की दिलाने व उन महिलाओं को याद करने का है जिन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम किया है। आधार की अध्यक्ष डॉ. गीता जैन ने कहा कि महिला दिवस का आयोजन तभी सार्थक होगा जब विश्व भर में महिलाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से संपूर्ण आजादी मिलेगी। समाज के हर महत्वपूर्ण फैसले में उनके नजरिए को महत्व दिया जाएगा। इस मौके पर ममता सिन्हा, दुर्गा बनर्जी, माधबी सेन गुप्ता, सुनैना कुमारी, किलकारी की श्रुति सुमन आदि ने भी विचार रखे। (साभार: दैनिक भास्कर, 10.3.2015)

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296